बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 117 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 17 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली के नेहरू प्लेस में मल्टी-लेवल पार्किंग का उद्घाटन, एक साथ खड़ी हो सकेंगी 660 कार और 350 बाइकें

नई दिल्ली । राजधानी के व्यस्त कारोबारी केंद्र नेहरू प्लेस में सोमवार को 6 मंजिला अत्याधुनिक मल्टी-लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति रही। उद्घाटन के साथ ही इस पार्किंग को आम जनता को समर्पित कर दिया गया है। यह मल्टी-लेवल पार्किंग पूरी तरह भूकंपरोधी तकनीक से तैयार की गई है और यहां सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी की व्यापक व्यवस्था की गई है। पार्किंग में आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। सभी मंजिलों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ईवी चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल ढांचा तैयार किया गया है, जिससे वे भी आसानी से इसका उपयोग कर सकें।

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

नई दिल्ली । दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में आज नई दिल्ली जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया. बैठक में जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे दिल्लीवासियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएं और भाजपा सरकार की नीतियों की विफलताओं को जनता के बीच उजागर करें. जिला अध्यक्ष महेंद्र मंगला द्वारा आयोजित इस बैठक में कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय अभियान चलाने और जनसंपर्क बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के अलावा पूर्व विधायक और लोकसभा प्रभारी हरी शंकर गुप्ता, AICC सचिव अभिषेक दत्त, ऑब्जर्वर शांति स्वरूप, हरनाम सिंह, आकांक्षा ओला और गौरी शंकर शर्मा सहित अनेक ब्लॉक अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे. इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान का हवाला देते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभिभावकों की सहमति के बिना निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे, जबकि इस मुद्दे पर अदालत पहले ही रोक लगा चुकी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग अभिभावकों का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने में विफल रहा. उन्होंने कहा कि कई निजी स्कूलों में बढ़ी हुई फीस न देने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र तक नहीं दिए जा रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है. देवेंद्र यादव ने कहा कि शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को नोटिस जरूर जारी किया कि फीस बकाया होने के कारण छात्रों का नामांकन रद्द न किया जाए, लेकिन मनमानी फीस वसूली और प्रवेश पत्र रोकने जैसे मामलों पर विभाग की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने फीस वृद्धि को लेकर कानून बनाने का व्यापक प्रचार तो किया, लेकिन उसे प्रभावी ढंग से लागू कराने में असफल रही. प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि दिल्ली सरकार निजी स्कूलों की मनमानी पर तुरंत रोक लगाए और गरीब तथा मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी करे. देवेंद्र यादव ने बताया कि सभी विधानसभाओं में BLA-1 के बाद प्रत्येक बूथ पर BLA-2 की नियुक्तियां लगभग पूरी हो चुकी हैं.

258 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के अंतर्गत मंडलम अध्यक्ष और सेक्टर इंचार्ज की नियुक्ति का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि BLA-2 की नियुक्तियां इसलिए की जा रही हैं ताकि एफआईआर प्रक्रिया में किसी भी वैध वोट को हटाया न जा सके और बूथ स्तर पर कांग्रेस की पकड़ और मजबूत हो.

अबू सलेम को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने सजा पूरी होने के दावे वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई बम धमाकों के आरोपी और कुख्यात गैंगस्टर अबू सलेम की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने खुद को तुरंत रिहा करने की मांग की थी। सलेम का दावा है कि वह 25 साल की सजा पूरी कर चुका है और पिछले 10 महीनों से उसे गैर-कानूनी हिरासत में रखा गया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सलेम के वकील से कहा कि वे इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट में ही उठाएं। बेंच ने साफ किया कि हाई कोर्ट ने अभी सिर्फ अंतरिम राहत देने से मना किया है, इसलिए सलेम को वहीं जाकर अपनी अंतिम बहस पूरी करनी चाहिए। सलेम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जुलाई 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्यता में उसकी 25 साल की सजा अभी पूरी नहीं हुई है। सलेम के वकील ने महाराष्ट्र जेल नियमों का हवाला देते हुए दलील दी कि अगर अच्छे बर्ताव के बदले मिलने वाली छूट को जोड़ लिया जाए, तो सलेम अपनी सजा काट चुका है। वकील ने यह भी आरोप लगाया कि जेल प्रशासन ने जो हलफनामा दिया है, उसमें गिनती की गलती है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान जस्टिस नाथ ने कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सलेम को समाज के लिए कुछ अच्छा न करने की वजह से 25 साल की सजा मिली थी। उसे टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (टीएडीए) जैसे गंभीर कानून के तहत दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने सलेम को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी और उसे हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए अर्जी देने की छूट दी।

कौन है अबू सलेम?

अबू सलेम 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस का दोषी है। उसे लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से भारत लाया गया था। भारत और पुर्तगाल के बीच हुए समझौते के तहत सलेम को मौत की सजा नहीं दी जा सकती और उसकी जेल की सजा 25 साल से यादा नहीं हो सकती।

जेल प्रशासन का क्या है कहना?

जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि केंद्र सरकार पुर्तगाल को दिए गए वादे को निभाने के लिए बाध्य है। जैसे ही सलेम की 25 साल की सजा पूरी होगी, उसे रिहा करना होगा। हालांकि, जेल प्रशासन के रिकॉर्ड के मुताबिक सलेम ने अब तक केवल 19 साल की सजा काटी है। सलेम को 1995 में हुए बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में भी उम्रकैद की सजा मिली हुई है। सलेम का कहना है कि उसकी कस्टडी 2005 से गिनी जानी चाहिए। अब इस मामले का भविष्य बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर टिका है।

प्रगति मैदान पहुंचने वाले जेएलएन स्टेडियम से सटल सेवा का उठाएं लाभ, चार सटल बसें शुरू

नई दिल्ली ।

एआई इम्पैक्ट समिट-2026 के लिए इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) ने एक महत्वपूर्ण सुविधा की शुरुआत की है। समिट में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों और आगंतुकों की सुविधा के लिए आईटीपीओ ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से प्रगति मैदान तक चार सटल बस सेवाओं का संचालन शुरू किया है। लोग अपनी गाड़ियां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास पार्क कर आसानी से इन सटल बसों का उपयोग करके प्रगति मैदान स्थित समिट स्थल तक पहुंच सकते हैं। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी जो समिट में शामिल होने के लिए दूर-दराज से आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट-2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अंतरराष्ट्रीय समिट में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्री और उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में सोमवार को शाम पांच बजे इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। यह एक्सपो एआई के व्यावहारिक प्रदर्शन का राष्ट्रीय मंच होगा, जहां नीति व्यवहार से मिलेगी, नवाचार व्यापक स्तर पर लागू होगा और प्रौद्योगिकी आम नागरिक तक पहुंचेगी। यह एक्सपो 70,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 10 एरेना में होगा, जो वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थानों, केंद्रीय मंत्रालयों, राय सरकारों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को एक साथ लाएगा। एक्सपो में ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान और अफ्रीका सहित 13 देशों के पवेलियन लगाए जाएंगे, जो एआई क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को प्रदर्शित करेंगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित 2.5 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। इस आयोजन का उद्देश्य वैश्विक एआई पारिस्थितिकी तंत्र में नई साझेदारियां स्थापित करना और व्यावसायिक अवसर उत्पन्न करना है।

दिल्ली में हर जमीन की होगी यूनिक आईडी, बनेगा लैंड आधार कार्ड; सीएम ने कहा- भूमि विवादों में आएगी कमी

नई दिल्ली ।दिल्ली में भूमि प्रबंधन को पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार हर जमीन को यूनिक पहचान देने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली की प्रत्येक जमीन को 14 अंकों का यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूएलपीआईएन) दिया जाएगा। यह व्यवस्था लैंड आधार कार्ड के रूप में काम करेगी, जिससे हर जमीन का डिजिटल हिसाब होगा और भूमि विवादों में कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से भूमि रिकॉर्ड भू-संदर्भित (जियो-रेफरेंस्ड) होंगे और सीमांकन विवादों में भारी कमी आएगी। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के खिलाफ एक मजबूत डिजिटल हथियार बताया। यह योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग की पहल है, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, लेकिन दिल्ली में इसे अब मिशन मोड में लागू किया जाएगा। दिल्ली में जमीन और राजस्व विभाग से जुड़ा ये महत्वपूर्ण सुधार होने जा रहा है।

फेज वाइज पूरी दिल्ली में होगा लागू

योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की आईटी शाखा को सौंपी गई है, जिसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग का तकनीकी सहयोग मिलेगा। सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरे दिल्ली क्षेत्र में यूएलपीआईएन लागू करेगी और इसके लिए एसओपी व समयसीमा भी तय की जा रही है।

आधुनिक तकनीक से बनेगा डिजिटल लैंड मैप

सीएम ने बताया कि भू आधार के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग से करीब दो टेराबाइट उच्च गुणवत्ता का भू-स्थानिक डेटा और ड्रोन से ली गई आर्थो-रेक्टिफाइड इमेजरी के आधार पर दिल्ली का नया डिजिटल लैंड मैप तैयार किया जाएगा।

भूमि विवादों और धोखाधड़ी पर लगेगी रोक

सीएम के मुताबिक, यूएलपीआईएन प्रत्येक भूखंड के लिए स्थायी पहचान होगी। इससे एक ही जमीन के बहु-पंजीकरण, धोखाधड़ी वाले लेन-देन और सीमांकन विवादों पर रोक लगेगी। विभिन्न सरकारी विभागों के बीच भूमि डेटा का बेहतर समन्वय संभव होगा। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अस्पष्ट रिकॉर्ड के कारण कानूनी विवादों में फंस जाते हैं।

दिल्ली की सड़कें होंगी चकाचक, धूल प्रदूषण पर लगाम के लिए एक्शन प्लान तैयार

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार धूल प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) से समझौता करेगी। इसके सहयोग से सड़क पर एंड-टू-एंड पेविंग वर्क (चौड़ाई में एक छोर से दूसरे छोर तक सुधार कार्य) और हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। यह कदम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के मानक के अनुसार सड़कों को विकसित करने की रणनीति के अंतर्गत उठाया जा रहा है। प्रस्तावित समझौते का ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने कुछ दिनों पहले विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि एंड-टू एंड-पेविंग आधुनिक सड़क निर्माण तकनीक है, जिसमें सड़क के मुख्य भाग के अलावा दोनों किनारों पर पैविंग ब्लाक, कंक्रीट या टाइल्स लगाई जाती हैं। धूल-मिट्टी उड़ने, पानी जमा होने और सड़क के किनारों को टूटने से बचाने के लिए यह तकनीक प्रयोग की जाती है। इसके साथ ही सड़कों व फ्लाईओवरों पर हरियाली बढ़ाई जाएगी। सड़कों के दोनों किनारे के अलावा सेंट्रल वर्ज पर भी हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी इस काम के लिए सीएक्यूएम के दिशा निर्देश के हिसाब से काम करेगा। योजना के अनुसार पीडब्ल्यूडी फ्लाईओवरों और सड़कों पर कोई खाली स्थान नहीं छोड़ेगा, ताकि धूल उड़ने की किसी भी संभावना को खत्म किया जा सके। उन स्थानों पर पौधारोपण और पेड़ों के नीचे खाली भूमि पर भी घास लगाकर हरियाली बढ़ाई जाएगी। कम हरियाली वाली सड़कों की पहचान करने के लिए विभाग जल्द सर्वे करेगा। पीडब्ल्यूडी के पास 1440 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। पीडब्ल्यूडी की योजना के अनुसार सड़कों की विकसित की गई हरियाली को व्यवस्थित रखने के लिए एक एजेंसी निर्धारित की जाएगी। एजेंसी सड़कों पर विकसित की गई हरियाली को नुकसान होने से बचाव करेगी। इसके

सीएम रेखा गुप्ता का हमला, पिछली सरकार ने डीटीसी को 65 हजार करोड़ के घाटे में डाला

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में पार्किंग और परिवहन व्यवस्था को लेकर पिछली सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक पार्किंग है और इस दिशा में मौजूदा सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में एक बेहद शानदार मल्टी लेवल पार्किंग बनकर तैयार हुई है, जो बहुत कम समय में पूरी की गई. यह इस बात का प्रमाण है कि अगर नीयत साफ हो तो विकास कार्य तेजी से पूरे किए जा सकते हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार का दुर्भाग्य यह रहा कि उसने कभी केंद्र सरकार और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के साथ मिलकर काम करने की कोशिश ही नहीं की. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री शीशमहल बनाने में व्यस्त थे, तब दिल्ली की जनता की सुध उपराज्यपाल ने ली. रेखा गुप्ता ने कहा कि आज उन्हें खुशी है कि जनता के एक वोट की ताकत ने दिल्ली में विकास कार्यों को फिर से गति दी है.

पार्किंग में आधुनिक तकनीक का हो रहा इस्तेमाल

मुख्यमंत्री ने बताया कि पार्किंग की बेहतर व्यवस्था के लिए सरकार ने आधुनिक तकनीक को अपनाया है. उन्होंने कहा कि चार महीने पहले पंजाबी बाग में ऑटोमेटिक मल्टी लेवल पजल कार पार्किंग का उद्घाटन किया गया था. इस पार्किंग में गाड़ी बस एंट्री गेट पर खड़ी करनी होती है और सिस्टम खुद गाड़ी को ऊपर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रख देता है. इसमें किसी व्यक्ति को अंदर जाने की

जरूरत नहीं पड़ती. इसी तरह ग्रेटर कैलाश में भी एक आधुनिक ऑटोमेटिक शटल कार पार्किंग शुरू की गई है, जो बहुत अच्छे से काम कर रही है.

पिछली सरकार में एक भी पार्किंग प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ

रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर पिछली सरकारों का रिकॉर्ड देखा जाए, तो उनके कार्यकाल में एक भी पार्किंग प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ. रानी बाग और शास्त्री पार्क में पार्किंग बनाने की योजनाएं जरूर बनीं, लेकिन उनकी फाइलें आज तक नहीं मिलीं. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने दिल्ली परिवहन व्यवस्था दिल्ली परिवहन निगम को करीब 65 हजार करोड़ रुपये के घाटे में डाल दिया. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पिछली सरकार ने एक निजी कंपनी DIMS से ऐसा अनुबंध किया, जिसमें पूरे डीटीसी का संचालन ही प्राइवेट हाथों में दे दिया गया. इसके लिए केवल कुछ डिपो चलाने के नाम पर 80 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि डीटीसी के अपने 7800 ड्राइवर और 4000 कंडक्टर खाली बैठे रहे. सरकार को दोहरा नुकसान हुआ एक तरफ अपने कर्मचारियों को बिना काम के वेतन देना पड़ा और दूसरी तरफ निजी कंपनी के ड्राइवरों को भी भुगतान किया गया. सीएम ने कहा कि जब उनकी सरकार ने यह अनुबंध खत्म किया और DIMS को बाहर का रास्ता दिखाया, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशानी होने लगी और धरना-प्रदर्शन शुरू हो गए. उन्होंने साफ कहा कि सरकार की जिम्मेदारी घाटे में चल रही डीटीसी को संभालने, अपने ड्राइवरों को काम देने, वेतन और पेंशन समय पर देने की है, न कि किसी निजी कंपनी को मुनाफा पहुंचाने की.

डीटीसी फिर से अपने पैरों पर खड़ी होने जा रही

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अब डीटीसी के सभी ऑपरेशन दोबारा सरकार के नियंत्रण में ले लिए गए हैं और कई सालों बाद डीटीसी फिर से अपने पैरों पर खड़ी होने जा रही है. अंत में उन्होंने दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए कहा कि जनता के वोट ने ऐसी सरकार चुनी है, जिसके कारण अब दिल्ली में रुके, अटके और भटके विकास कार्य फिर से शुरू हो पाए हैं.

राष्ट्रगीत बनाम राष्ट्रगान

अदालत ने ऊंचे आसन से आगे की ओर कुछ झुक कर पूछा--भाई राष्ट्रगीत, अदालत तुमसे ही मुख्तसर में सुनना चाहती है कि तुम्हारी शिकायत क्या है? वंदे मातरम ने कुछ नाराजगी के साथ कहा कि संक्षेप में शिकायत यही है कि इस राष्ट्रगान ने मेरा हक मार लिया है, मेरा सम्मान चुरा लिया है। बस इतनी विनती है कि मेरा हक, मेरा सम्मान वापस दिलाया जाए। आगे मेरा पक्ष, एडवोकेट जनरल साहब रखेंगे। अदालत ने राष्ट्रगान की तरफ मुखातिब होकर पूछा—और भाई राष्ट्रगान इनकी शिकायत के संबंध में आपको कुछ कहना है? जन गण मन ने शांति से कहा, मुझे तो इस शिकायत का सिर-पैर ही समझ में नहीं आ रहा। राष्ट्रगीत का सम्मान अपनी जगह है। ज्यादातर शासकीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से शुरुआत होती है, तो राष्ट्रगीत पर समापन। और इस भाई का सम्मान मैं क्यों चुराने लगा? विनती है कि यह दावा खारिज किया जाए। आगे मेरा पक्ष, टैगोर साहब रखेंगे। अदालत ने कहा कि एक राष्ट्रगीत है और एक राष्ट्रगान, दोनों का अपना-अपना दर्जा है। छियत्तर साल से यह व्यवस्था बिना किसी विवाद के चलती आ रही थी। फिर दिक्कत क्या आ गयी? बस एडवोकेट जनरल शुरू हो गए। दोनों का अपना-अपना दर्जा में ही तो प्राब्लम है। यह धारणा भी गलत है कि छियत्तर साल से सब ठीक चल रहा था। हम तो कहेंगे कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मेरे मुवक्किल, वंदे मातरम् को कभी न्याय मिला ही नहीं। पहले, आजादी से पहले नेहरू वगैरह ने षड्यंत्र कर के, धार्मिक सद्भाव के नाम पर बेचारे गीत को काट-छांटकर अपनाया। फिर आजादी के बाद, उसी षड्यंत्र के तहत, कटे-छंटे गीत को भी अपनाया, तो राष्ट्रगीत बनाकर, जबकि राष्ट्रगान के आसन पर जन गण मन को लाकर बैठा दिया गया। और इतना भी जैसे काफी नहीं हो, बेचारे वंदे मातरम के गाए-बजाए जाने को न तो सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य किया गया और ना ही उसके संबंध में कोई नियम वगैरह बनाए गए। राष्ट्रगीत को लोगों के रहमो-करम पर छोड़ दिया गया! ये मेरे मुवक्किल की हकमारी नहीं तो और क्या थी? अदालत ने उसका पक्ष सही तरह से समझने के लिए पूछा—क्या राष्ट्र गीत को गाया/ बजाया ही नहीं जा रहा था, सिर्फ राष्ट्रगान को ही गाया/ बजाया जा रहा है? क्या राष्ट्र गीत के गाए/ बजाए जाने पर किसी तरह की घोषित/ अघोषित पाबंदी लगी हुई है? एडवोकेट जनरल ने कुछ खीझकर कहा--इससे क्या फर्क पड़ता है? राष्ट्र गीत के गाने/ बजाने को अगर लोगों के रहमो-करम पर छोड़ दिया जाता है, तो इसमें उसका सम्मान कहां है? फिर ये कैसा सम्मान है, जिसमें राष्ट्रगीत को काट-छांटकर गाया जाए? हमारा तो पक्ष है कि वंदे मातरम् के साथ शासकीय अन्याय की शुरुआत तभी हो गयी थी, जब उसके दावे को अनदेखा कर, जन गण मन को राष्ट्रगान बनाया गया था। पचहत्तर साल बाद, कम से कम अब उस अन्यायपूर्ण निर्णय को पलटा जाना चाहिए और वंदे मातरम को पूर्ण न्याय दिलाया जाना चाहिए। अदालत ने अब टैगोर की तरफ रुख किया। टैगोर ने धीरे-धीरे, समझाने के स्वर में अपनी बात शुरू की। वंदे मातरम और जन गण मन, मुझे दोनों गीत बहुत प्यारे हैं। जन गण मैंने लिखा है और वंदे मातरम् मैंने ही सबसे पहले आजादी की लड़ाई में लगी कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। बंकिम की इस कविता के पहले दो पद, अद्भुत हैं--मां के रूप में राष्ट्र की आराधना। पर बाद के पद, जो बंकिम बाबू ने अपने उपन्यास में इस कविता को शामिल करते हुए जोड़े थे, इस राष्ट्र माता को, पहले बंग माता और फिर काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों का रूप दे देते हैं और कविता के दायरे को एक प्रकार से सीमित कर देते हैं। पहले पदों की सर्व स्वीकार्यता के विपरीत, इन बाद के पदों की सर्व स्वीकार्यता नहीं थी, न जन साधारण में और न स्वतंत्रता आंदोलन में। इसीलिए, मेरे सुझाव पर कांग्रेस ने वंदे मातरम के पहले दो पदों को अपनाया था और बाद में इन्हीं पदों को राजेंद्र बाबू के प्रस्ताव पर, संविधान सभा ने राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। इस निर्णय में वंदे मातरम के साथ कोई अन्याय नहीं, उसके राष्ट्रीय भावना के अनुरूप हिस्से का सम्मान ही था। रही बात जन गण मन की तो, उसके संबंध में मेरा कुछ भी कहना अजीब सा लगेगा। हां! इतना जरूर याद दिला दूं कि काटकर तो जन गण मन को भी अपनाया गया था। मूल कविता में और भी कई पद हैं, जिन्हें निर्णयकर्ताओं ने छोड़ दिया। राष्ट्रगीत हो या गान, उसकी सहज गेयता, सघनता, सहज व्याप्ति, सभी का ध्यान रखा जाता है। एडवोकेट जनरल ने खीझ कर कहा, ये सब कहने-सुनने की बातें हैं। असली मुद्दा कविता को काटने न काटने का है ही नहीं। मुद्दा काटने की वजह का है। काटकर ही सही, वंदे मातरम को राष्ट्रगान क्यों नहीं बनाया गया और जन गण मन को ही राष्ट्रगान क्यों बनाया गया? जन गण मन को काटा गया होगा, राष्ट्रगान के आदर्श आकार में लाने के लिए, पर वंदे मातरम को क्यों काटा गया था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसे काटा गया था, अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण के लिए यानी मुसलमानों के लिए। इसी वजह से उसे राष्ट्रगान भी नहीं बनाया गया। मुसलमानों ने वंदे मातरम् का हक छीना था, हमारी मांग है कि उसे हक वापस दिलाया जाए। टैगोर ने पूछा--तो आपको वंदे मातरम् को इसीलिए राष्ट्रगान बनवाना है कि वह मुसलमानों को चिढ़ाएगा? राष्ट्रीय आंदोलन में इस तरह तो कोई नहीं सोचता था। वर्ना राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, दो-दो गीतों को क्यों अपनाया जाता; और किसी देश ने तो नहीं अपनाया है। दूसरी ओर से एडवोकेट जनरल ने चिढ़ कर कहा, ये मेरे शब्द नहीं हैं। हां! जो भी भारत से प्रेम करता है, वह वंदे मातरम खुशी से गाएगा। जो नहीं गाएगा, वह भारत माता से प्रेम नहीं करता है—इति सिद्धम। देश प्रेम की परीक्षा से डरने वालों के लिए, हम अपना राष्ट्रगान नहीं बदल देंगे! टैगोर ने धीरे से कहा- पर ऐसे तो वंदे मातरम राष्ट्रगीत नहीं, विभाजन का गीत हो जाएगा। एडवोकेट जनरल ने चिढ़कर कहा, राष्ट्र भले बंट जाए, हमें गीत पूरा चाहिए। जन गण मन ने दु:खी होकर कहा, इसी को बना दें राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान सब, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। अगली तारीख को एडवोकेट जनरल ने अदालत से प्रार्थना की कि उसके मुवक्किल की प्रार्थना सरकार ने पूरी कर दी है, इसलिए उसे अपनी याचिका वापस लेने की इजाजत दी जाए। राष्ट्रगीत का दर्जा, राष्ट्रगान से ऊपर कर दिया गया है और उसे पूरा गाना अनिवार्य कर दिया गया है। अदालत से निकलते-निकलते वंदे मातरम ने ताना मारा—राष्ट्रगान, और कब तक! टैगोर ने बुदबुदा कर कहा—महात्मा सही थे, इन्होंने तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भी लड़ा दिया।

आओ कि इक ख्वाब बुनें

चलिए, एक ख्वाब देखें। क्या ख्वाब में भी यह संभावना हो सकती है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य आने वाले समय में कोई परिसंघ (कान्फेडरेशन) या महासंघ बनेगा? फिलहाल आज के हालात इसकी गवाही नहीं देते कि आने वाले वक्त में ऐसा कोई परिसंघ या महासंघ इन तीन देशों के बीच बनेगा? साझी विरासत और साझेदारी के अनेक पुल थे जो हमारी अपनी ही सरकारों और अपने ही लोगों ने तोड़ डाले। मगर उन साझे पुलों के खण्डहर एवं निशानियां तो आज भी मौजूद हैं। चलिए, साझे पुलों पर एक नजर तो डाल लें। लाहौर के किले का 'लव-मंदिर' गवाही देता है कि यह शहर भगवान राम के बड़े पुत्र लव ने बसाया था। पाकिस्तान की सरकार वहां के इतिहासकार व पुरातत्वविद भी यह मानते हैं कि लाहौर महाराजा लव ने बसाया था और कसूर की स्थापना लव के छोटे भाई कुश ने की थी। सिख धर्म की पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव ने वर्तमान पाकिस्तान स्थित श्री ननकाना साहब में जन्म लिया था और वह जिस स्थान पर ज्योति-ज्योत समाए थे, वह स्थान भी श्री करतारपुर साहब वर्तमान पाकिस्तान में ही है। हमारे शहीदे आज़म भगत सिंह का जन्म स्थान भी वर्तमान पाक में है और उन्होंने अपने दोनों हमजोलियों सुखदेव व राजगुरु के साथ लाहौर की सेंट्रल जेल में ही फांसी के फंदे पर अंतिम सांस ली थी। यह सिलसिला बहुत लम्बा है। कदम-कदम पर इतिहास के पन्ने साझी विरासत की गवाही देते हैं। कहीं कटासराज के बहाने तो कहीं मुल्तान के आदित्य मंदिर (मुल्तान) के बहाने, कहीं किस्सों, कहानियों, लोकगीतों, साहित्यकारों के बीच साझेदारी खत्म नहीं हो पाई। पिछली सदी में ही सर गंगाराम, सरदार दयाल सिंह मजीठिया, लाला लाजपत राय और उनका गुलाब देवी अस्पताल आदि महान शख्सियतों के नाम साझेदारी में बकायदा बने हुए हैं। जब भी मंटो, फैज, अमृता, साहिर, बड़े गुलाम अली खान, रेशमा व मेंहदी हसन की बात चलती है तो भी साझी विरासत करवटें लेती है। इन दिनों राखीगढ़ी की चर्चा के साथ-साथ हड़प्पा व मोहेन्जोदाड़ो की पुरातात्विक सांझेदारी, पुराना तक्षशिला, व्याकरण के धुरंधर विद्वान पाणिनी, सबका जिक्र साझे पुलों के रूप में हो रहा है। मगर यह भी एक हकीकत है कि इतिहास में 'रिवर्स-गियर' नहीं होते। वैसे यह भी हकीकत ही है कि जहां पुराने रूप में लौटना नामुमकिन हो वहां कुछ साझे पुल या नए सब-स्टेशन बनाए जा सकते हैं। इसी अवधारणा को विशेष रूप में समर्थन देने वालों में भाजपा के शिखर पुरुष लालकृष्ण अडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे लेकिन पाकिस्तान में सैनिक-जुंडली व आईएसआई सरीखी संस्थाओं ने ऐसे सभी प्रयासों को 'पंक्चर' किया। 'सदा-ए-सरहद' और 'समझौता एक्सप्रेस' सरीखे ईमानदाराना प्रयास भी असफल रहे। अतीत में इससे पूर्व भी सांसद एचवी कामथ, डॉ. राममनोहर लोहिया व आचार्य कृपलानी ने भी प्रयास किए थे। इसी सिलसिले में क्रिकेट, हॉकी व 'लिटरेचल फैस्टिवल्स' की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उधर 'ढाके की मलमल' वाला बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बन गया। आप अनुमान लगाएं एक वक्त का दौर, काज़ी नज़रूल इस्लाम (वर्तमान बांग्लादेश) रवींद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद, फैज, मंटो, कुर्रतुल एन हैदर, अमृता प्रीतम, साहिर, इस्मत चुगताई आदि इसी एक 1947 पूर्व वाले एक ही देश का हिस्सा थे। 1947 में मजहब के आधार पर देश के दो टुकड़े हुए और फिर 1971 में पाकिस्तान भी दो हिस्सों में बंट गया, मगर यह दूसरा विभाजन 'मजहब' के आधार पर नहीं हुआ। यह भाषा के आधार पर हुआ। बांग्लादेश के नाम से अस्तित्व में आए इस तीसरे राष्ट्र का गठन बंगला भाषाई व पंजाबी भाषाई क्षेत्र के टकराव के रूप में आया है। 'टुकड़े-टुकड़े' होने का यह सिलसिला अभी भी वर्तमान पाकिस्तान में भी जारी है। वहां एक ओर बलूचिस्तान की सुगबुगाहट जारी है तो दूसरी ओर पख्तून भी अलग होने के लिए बेचैन है। उधर आतंकी संगठनों ने लाहौर, बहावलपुर व पाक-अधिकृत कश्मीर में अपनी-अपनी समानांतर सरकारें चला रखी हैं। तीनों राष्ट्रों में भारत विकास, नवनिर्माण एवं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मजबूत है मगर भाषा, सम्प्रदाय व मजहब के आधार पर एकरूपता अभी भी एकाध दशक की मोहताज है। यह तो तय है कि इस देश के और टुकड़े अब नामुमकिन हैं। देश तो एक ही रहेगा मगर खींचतान कुछ अवधि तक चल सकती है। वर्तमान ढांचे में यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि फिलहाल इसका कोई विकल्प नहीं है। जो विकल्प है वो भी 'भोथरे' हो चुके हैं। इस पूरे उपमहाद्वीप में देर-सवेर एक 'कान्फैडरेशन' या 'महासंघ' की आवश्यकता शिद्दत से महसूस होने लगेगी। इस दिशा में जाने का थोड़ी पहलकदमी का रास्ता साहित्य, पुरातत्व, क्रिकेट व हॉकी से ही निकलेगा। तब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई, बड़े गुलाम अली खान, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर व किशोरीबाई अमोनकर का आलाप ही काम आएगा। लता ताई, नूरजहां, मुहम्मद रफी, किशोर दा, आशा भोंसले, आबिदा, रेशमा इस उपमहाद्वीप की साझी संस्कृति की खुशबू को कब तक दबाकर रखेंगे। लव-कुश के बिना रामकथा अधूरी है। चलिए पंडित रवि शंकर व एआर रहमान (अब शायद पछता रहे होंगे) का साझा सुर-संगम भी इस माटी की सोंधी गंध में रचा बसा है।

सम्पादकीय...

मस्जिद' और 'घुसपैठिए' की राजनीति

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले धर्म ध्वजा फहराने की कवायद तेज हो गई है। आर.एस.एस. के सौ साल पूरा होने के अवसर पर राज्य भर में होने वाले हिन्दू सम्मेलन को भाजपा हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने के विशेष अवसर और चुनाव अभियान की तरह इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदुत्व के मोर्चे को भाजपा के लिए खुला नहीं छोड़ा है। पिछले दिसम्बर में कोलकाता के न्यू टाउन में विशाल 'दुर्गा आंगन' का शिलान्यास करके उन्होंने हिंदू मतदाताओं को भाजपा के खेमे में खिसकने से रोकने की जो बड़ी पहल शुरू की थी, उसे बंगाली अस्मिता से जोड़ने के अभियान पर लगातार आगे बढ़ा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास करके ममता के सामने एक नई चुनौती जरूर खड़ी कर दी है और भाजपा इसे भी भुनाने की कोशिश में जुट गई है। बंगाल की राजनीति में इस समय कई सवाल गूंज रहे हैं। क्या हिंदू सम्मेलन और हुमायूं कबीर के बहाने भाजपा राज्य के 70 प्रतिशत हिंदू मतदाताओं को ममता के खिलाफ खड़ा कर पाएगी? क्या हुमायूं कबीर और अन्य मुस्लिम पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं को बांटने में सफल हो पाएंगी? या फिर अल्पसंख्यकों की रक्षा और दुर्गा आंगन की मशाल लेकर ममता एक बार फिर से जीत का झंडा फहराने में सफल होंगी? ममता की चुनौती - ममता इस समय कई मोर्चों पर जूझ रही हैं। एस.आई.आर. यानी विशेष मतदाता सूची सर्वेक्षण में मुसलमानों और अत्यंत गरीब लोगों का नाम कटने के मुद्दे पर उनके कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लड़ रहे हैं और वह खुद सुप्रीम कोर्ट तक हाजिरी लगा चुकी हैं। बिहार, जहां एस.आई.आर. की शुरुआत हुई या फिर अन्य राज्य, जहां यह प्रक्रिया अभी चल रही है, वहां बंगाल जैसी जुझारू लड़ाई दिखाई नहीं दे रही। भाजपा का अभियान चार मुद्दों पर केंद्रित है। 'बंगाल में हिंदू खतरे में है', भाजपा का मुख्य अभियान इसी नारे पर केंद्रित है। बंगाली हिंदुओं को बताया जा रहा है कि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। बांग्लादेश की सीमा से लगे कुछ जिले, जहां मुस्लिम आबादी 50 फीसदी या ज्यादा है, का उदाहरण देकर बताया जा रहा है कि बंगाली हिंदू जल्दी ही राज्य में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ का शोर मचाकर हिंदुओं की चिंता बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आर.जी. कर मैडिकल कालेज में एक डॉक्टर से बलात्कार का उदाहरण देकर बताया जा रहा है कि बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं। चौथा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। शिक्षक भर्ती घोटाला जैसे मामले इसके उदाहरण के रूप में पेश किए जा रहे हैं। ममता सी.बी.आई. और ई.डी. जैसी केंद्र सरकार की एजेंसियों से सीधे टक्कर ले रही हैं। क्या मुस्लिम वोट बंटेगा - चुनाव में हिंदू-मुस्लिम मुद्दा बन जाए तो भाजपा फायदे में रह सकती है। लेकिन ममता आसानी से ऐसा होने देने के मूड में नहीं हैं। लेकिन उनके सामने मुस्लिम वोटों का बंटवारा एक बड़ी चुनौती है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की पहल से मुस्लिम मतदाताओं के बीच हुमायूं कबीर की लोकप्रियता बढ़ी है। वैसे हुमायूं मुसलमानों के कोई प्रतिष्ठित नेता नहीं रहे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने तृणमूल के टिकट पर जीता था। 2019 में वह भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ कर तीसरे नंबर पर रहे थे। टी.एम.सी. से निकाले जाने के बाद उन्होंने अलग जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) बना ली है और 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं।

एचबीए1सी टेस्ट पर नया अध्ययनः डायबिटीज की चुनौतियां

डायबिटीज, जिसे आधुनिक युग की महामारी कहा जा रहा है, भारत में करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत दुनिया का डायबिटीज कैपिटल है, जहां 10 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। डायबिटीज के निदान और नियंत्रण के लिए एचबीए1सी (ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन) टेस्ट को 'सोने का मानक' माना जाता रहा है। यह टेस्ट पिछले दो-तीन महीनों की औसत ब्लड शुगर लेवल को मापता है, जो आसान, गैर-आक्रामक और विश्वसनीय लगता है। लेकिन फरवरी 2026 में 'द लैंसेट रीजनल हेल्थ-साउथ-ईस्ट एशिया' जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन ने इस धारणा को चुनौती दे दी है। यह अध्ययन, जो विशेष रूप से भारतीय और दक्षिण एशियाई आबादी पर केंद्रित है, चेतावनी देता है कि एनीमिया, हीमोग्लोबिन विकृतियों और अन्य कारकों के कारण एचबीए1सी टेस्ट गलत निदान कर सकता है, जिससे डायबिटीज का पता चार साल तक देरी से चल सकता है। यह अध्ययन, प्रोफेसर अनूप मिश्रा और उनके सहयोगियों द्वारा लिखित, एचबीए1सी की सीमाओं पर गहन समीक्षा करता है। भारत में एनीमिया एक महामारी है-राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार, 50 प्रतिशत से अधिक वयस्क महिलाएं और 25 प्रतिशत पुरुष एनीमिया से प्रभावित हैं। एनीमिया आयरन की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या घटाता है, जिससे एचबीए1सी का स्तर कृत्रिम रूप से ऊंचा हो जाता है। परिणामस्वरूप, जो व्यक्ति डायबिटीज से ग्रस्त नहीं है, उसे गलत तरीके से डायबिटीज का मरीज घोषित कर दिया जा सकता है। इसके विपरीत, हीमोग्लोबिनोपैथी (जैसे थैलेसीमिया, जो भारत में 4 प्रतिशत आबादी को प्रभावित करता है) या जी6पीडी की कमी एचबीए1सी को कम दिखा सकती है, जिससे वास्तविक डायबिटीज वाले मरीजों का निदान देरी से होता है। अध्ययन के अनुसार, दक्षिण एशियाई लोगों में एचबीए1सी और वास्तविक ब्लड ग्लूकोज के बीच सहसंबंध कमजोर है। उदाहरण के लिए, एनीमिया वाले क्षेत्रों में एचबीए1सी पर निर्भरता से डायबिटीज का निदान 20-30 प्रतिशत मामलों में गलत हो सकता है। यह न केवल निदान को प्रभावित करता है, बल्कि उपचार को भी, अनावश्यक दवाएं या देरी से उपचार से जटिलताएं जैसे हृदय रोग, किडनी फेलियर बढ़ सकती हैं। अध्ययन की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जैसे विकासशील देशों में जहां एनीमिया और आनुवंशिक विकार आम हैं, एचबीए1सी को अकेले इस्तेमाल करना जोखिमपूर्ण है। यह पश्चिमी आबादी पर आधारित मानकों को सीधे लागू करने की भूल को उजागर करता है। भारत में डायबिटीज का बोझ पहले से ही भारी है। आईसीएमआर के अनुसार, 2030 तक यह 13.5 करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन यह अध्ययन बताता है कि लाखों लोग अनदेखे डायबिटीज से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि एचबीए1सी पर अंधविश्वास ने अन्य टेस्ट जैसे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट (ओजीटीटी) या फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज (एफपीजी) को पीछे धकेल दिया है।

विशेष रूप से ग्रामीण भारत और महिलाओं के लिए यह खतरा अधिक है, जहां एनीमिया दर 60 प्रतिशत से ऊपर है। देरी से निदान से न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य बिगड़ता है, बल्कि स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ भी बढ़ता है। चिंता का मतलब घबराहट नहीं होना चाहिए। यह अध्ययन एक जागृति का संकेत है। भारतीयों की आनुवंशिक संरचना-जैसे 'थ्रिफ्टी जीन' हाइपोथेसिस, जो दक्षिण एशियाई लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देती है-पहले से ही डायबिटीज को जन्मभूमि बनाती है। लेकिन एचबीए1सी की सीमाएं जानकर हम बेहतर रणनीति बना सकते हैं। अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे, तो 'साइलेंट किलर' जाने जाने वाली डायबिटीज और घातक हो जाएगी। गौरतलब है कि फार्मा उद्योग, जो डायबिटीज मार्केट से सालाना अरबों-खरबों कमाता है, इस अध्ययन से हलचल में आ सकता है। भारत में एचबीए1सी टेस्ट किट्स का बाजार 500 करोड़ रुपये से अधिक का है। इस अध्ययन से बड़ी कंपनियों की बिक्री प्रभावित हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर अब कॉम्बिनेशन टेस्ट की सिफारिश करेंगे। संभावना है कि फार्मा कंपनियां वैकल्पिक डायग्नोस्टिक टूल्स पर निवेश बढ़ाएंगी। दवाओं के मामले में भी सदियों से चली आ रही दवाओं पर सीधा असर कम होगा, क्योंकि निदान गलत होने से उपचार की शुरुआत प्रभावित होगी, लेकिन एक बार निदान हो जाए तो दवाओं को उसी मुताबिक दिया जाएगा। हालांकि, फार्मा इंडस्ट्री की लॉबी इस अध्ययन को चुनौती दे सकती है, यह दावा करते हुए कि एचबीए1सी अभी भी उपयोगी है। वहीं वैश्विक स्तर पर, कुछ कंपनियां, जो अलग तरह के जांच उपकरण व दवाएं बेचती हैं, इस नए अध्ययन को मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। कुल मिलाकर, यह उद्योग के लिए एक अवसर भी साबित हो सकता है, जो बाजार को नया आयाम देगा। लेकिन अगर प्रतिक्रिया नकारात्मक हुई, तो नियामक दबाव बढ़ सकता है। भारतीय डॉक्टर इस अध्ययन से सहमत हैं, लेकिन घबराहट की बजाय सतर्कता की वकालत करते हैं।

प्रोफेसर अनूप मिश्रा, अध्ययन के मुख्य लेखक और फोर्टिस सीकेडी हॉस्पिटल के चेयरमैन, कहते हैं, -एचबीए1सी पर पूर्ण निर्भरता से डायबिटीज की स्थिति का गलत वर्गीकरण हो सकता है। कुछ लोग अनुचित रूप से देरी से निदान हो सकते हैं।- एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक सर्वे में 70 प्रतिशत डॉक्टरों ने कहा कि एनीमिया वाले मरीजों में ओजीटीटी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस अध्ययन के बाद, डॉक्टरों का मत है कि एचबीए1सी उपयोगी है, लेकिन अकेला नहीं। वो मानते हैं कि मिली-जुली प्रक्रिया के तहत डायबिटीज जैसी बीमारी का निदान किया जा सकता है। यह अध्ययन हमें निष्क्रियता से हटाकर सक्रियता की ओर ले जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर आप एचबीए1सी टेस्ट करवा रहे हैं, तो सीबीसी (कम्प्लीट ब्लड काउंट) से एनीमिया भी चेक जरूर करवाएं। अगर एनीमिया है, तो ओजीटीटी या एफपीजी पर स्विच करें। इसके साथ ही 30 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों को हर साल कम से कम दो टेस्ट-एफपीजी और एचबीए1सी करवाने चाहिए। डायबिटीज का 80 प्रतिशत जोखिम रोकथाम योग्य है। दैनिक 30 मिनट व्यायाम, फाइबर-युक्त आहार (दालें, सब्जियां) और वजन नियंत्रण अपनाएं। अध्ययन दिखाता है कि भारतीयों में वजन बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ता है। एनीमिया रोकने के लिए आहार में पालक, गुड़ और पौष्टिक आहार शामिल करें, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह से। अस्पतालों और सामाजिक संस्थाओं को सामुदायिक स्तर पर कैंप लगाने चाहिए, जिससे कि जागरूकता बढ़े। सस्ते व आसानी से उपलब्ध ग्लूकोमीटर या ऐप्स से घर पर मॉनिटरिंग करें। ये कदम न केवल डायबिटीज को नियंत्रित करेंगे, बल्कि समग्र स्वास्थ्य भी सुधारेंगे। यह लैंसेट अध्ययन एचबीए1सी को खारिज नहीं करता, बल्कि इसकी सीमाओं को उजागर करता है। भारतीयों के लिए यह एक जागृति का क्षण है, चिंता करें, लेकिन उचित कार्रवाई भी करें। डायबिटीज से लड़ाई में सटीक निदान पहला कदम है। अगर हम इसे अपनाएं, तो भारत न केवल डायबिटीज कैपिटल से उबर सकता है, बल्कि हेल्थकेयर का वैश्विक मॉडल भी बन सकता है। समय है सोच बदलने का-स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए।

उलटा पड़ सकता है राहुल पर मुक़दमे का दांव

राहुल गांधी वैसे तो मुकदमों के आदी हो गए हैं। देश का शायद ही कोई राज्य होगा, जहां उनके खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने जो नया मुकदमा दर्ज किया है वह कायदे से उनके लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि वह इस मुकदमे के जरिए दबाव बढ़ाएगी। वह दबाव राहुल के साथ साथ कुछ दूसरे लोगों पर भी हो सकता है। यह मुकदमा लोकसभा में पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब लेकर जाने का है। बहरहाल, दिल्ली पुलिस जब इस बात की जांच करेगी कि राहुल गांधी को किताब कहां से मिली तो उसके साथ कई चीजों की जांच होगी। जांच की आंच पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे तक भी पहुंचेगी क्योंकि अगर प्रकाशक ने नहीं लीक की तो किसने लीक की। सरकार के संसदीय प्रबंधक उम्मीद कर रहे हैं कि इससे वे कांग्रेस और विपक्ष पर दबाव बना पाएंगे। दूसरी ओर राहुल गांधी की टीम का कहना है कि यह विवाद, जितना बढ़ेगा उतना सरकार को नुकसान होगा। लोगों के मन में सवाल उठेगा कि आखिर सरकार क्यों एक पूर्व सेना प्रमुख की किताब की बातें बाहर आने से रोकना चाहती है। लोगों को यकीन हो गया कि पूर्व सेना प्रमुख कुछ ऐसा बताना चाहते हैं, जो सरकार छिपाना चाहती है तो उसका उलटा असर होगा। सेना को लेकर सरकार, जो भी नैरेटिव बनाती है वह खराब होगा। इसलिए मुकदमा दोधारी तलवार है। सरकार को उलटा भी पड़ सकता है।

अजित पवार की मौत से जुड़े सवाल

शरद पवार के पोते और उनकी पार्टी के विधायक रोहित पवार ने अपने चाचा अजित पवार की मौत के पीछे साजिश की बात कही है। बीते मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन देकर रोहित ने आरोप लगाया कि अजित पवार के विमान हादसे के पीछे बड़ी साजिश है। जिस समय रोहित पवार पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दे रहे थे उसी समय सुनेत्रा पवार ने औपचारिक रूप से उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। अभी उनकी या उनके दोनों बेटों की तरफ से इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। इसीलिए सवाल है कि शरद पवार खेमे के नेता क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? खुद शरद पवार ने पहले दिन साजिश की बात से इनकार किया था। बहरहाल, रोहित पवार ने यह सवाल भी उठाया कि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वह दो दिन पहले सूरत क्यों गया था? उन्होंने पायलट सुमित कपूर के आचरण का सवाल उठाया और कहा कि वे शराब पीने की लत की वजह से कई बार विवाद में रहे हैं। पहले उनको अजित पवार का विमान लेकर बारामती नहीं जाना था, लेकिन अचानक पहले से तय पायलट की जगह उनको भेजा गया। रोहित ने कहा कि हादसे से पहले पायलट ने %मे डे' अलर्ट नहीं किया, बल्कि वे पूरी तरह से शांतचित्त बने रहे। पहली नजर में सवाल जायज लग रहे हैं लेकिन अगर ये आरोप लगाते समय अजित पवार की पत्नी या बेटे भी साथ होते तो इनकी गंभीरता बढ़ जाती।

एआई सम्मेलन के लिए होटल की मारामारी

राजधानी दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 16 से 20 फरवरी के होने जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर की एआई कंपनियां और स्टार्टअप्स के लोग आ रहे हैं। इस मौके पर एआई अनुसंधान संगठन ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन सैकड़ों सीईओ और टेक्नोक्रेट भी दिल्ली आएंगे। लेकिन इस सम्मेलन को लेकर भारत में अभी तक मुख्य रूप से जो खबर चर्चा में है वह होटलों हो रही मारामारी को लेकर है। इस सम्मेलन के लिए भारत की क्या तैयारी है या भारत की कितनी कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी और इससे भारत में एआई इकोसिस्टम पर क्या असर होगा, इसकी चर्चा की बजाय होटल के कमरे महंगे होने की खबर है। दिल्ली के सभी पांच सितारा होटल 16 से 20 फरवरी तक के लिए भर गए हैं और एक भी कमरा खाली नहीं है। यह भी खबर है कि कमरे का किराया जो पहले 20 हजार रुपये था, वह अब 50 हजार रुपये से ऊपर है और 40 हजार के सूट रूम का किराया डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा हो गया है। सवाल है कि क्या इतना बड़ा सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है तो सरकार को सर्ज प्राइसिंग पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए? लेकिन भारत में हर मौके पर चाहे वह इस तरह का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो या कोई आपदा हो, विमानन कंपनियों से लेकर होटल वाले और कैब सर्विस वाले अनाप शनाप किराया वसूलने लगते हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय मेहमानों को परेशानी होती है और भारत की छवि पर भी असर पड़ता है।

असम में भाजपा सिर्फ हिंदू-मुस्लिम के सहारे

असम में कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं लेकिन वहां दूसरे सारे मुद्दे गौण हो गए होते जा रहे हैं। वहां 10 साल से भाजपा की सरकार है और इन 10 सालों में केंद्र में भी भाजपा की ही सरकार रही है। लेकिन 10 साल से अपनी इस डबल इंजन सरकार के कामकाज की बजाय भाजपा सिर्फ हिंदू-मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उसकी जो चुनाव सामग्री तैयार की जा रही है उसमें सबका फोकस हिंदू-मुस्लिम पर है। एक प्रयोग के तौर पर पिछले दिनों एआई से बना एक वीडियो वायरल कराया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा गोल टोपी और दाढ़ी वाले दो मुस्लिम दिखते लोगों पर बंदूक से निशाना साध रहे थे। बाद में उसे हटा लिया गया है। असल में पहले थोड़ा बारीक तरीके से यह मुद्दा उठाने की कोशिश की गई थी। घुसपैठियों के नाम पर हिंदू-मुस्लिम विभाजन का प्रयास हुआ। फिर मियां मुस्लिम वाला जुमला आया। कहा गया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को मियां मुस्लिम कहा जाता है। सरमा ने उन्हें प्रताड़ित करने की सार्वजनिक अपील की। अब लग रहा है कि उससे भी बात नहीं बन रही है तो सीधे गोली मारने का नैरेटिव बनाया जा रहा है। सरमा ने इसी तरह का जहरीला प्रचार 2024 के झारखंड चुनाव में भी किया, लेकिन भाजपा बुरी तरह से चुनाव हारी। वहां घुसपैठ और जमाई जिहाद का उनका मुद्दा नहीं चल पाया। अब देखना है कि असम में वे इस मुद्दे को कितना चला पाते हैं।

सब चाहते थे कि पाकिस्तान मैच खेले

आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकती, पाकिस्तान के संदर्भ में यह बात भारत सरकार के शीर्ष नेता अक्सर कहते रहते हैं। इसी तर्ज पर भारत के क्रिकेट प्रशासक और प्रसारणकर्ता भी कहते हैं कि आतंकवाद और क्रिकेट दोनों साथ-साथ नहीं चल सकता। लेकिन बात जब धंधे की आती है तो सब चलने लगता है। इस बार भी करीब 10 दिन के ड्रामे के बाद टी20 विश्व कप में पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो में भारत से मैच खेलने को तैयार हो गया। यह भी कमाल का संयोग है, जो आईसीसी के हर टूर्नामेंट में होता है कि भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रखे जाते हैं। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि कम से कम एक मैच दोनों देशों के बीच जरूर हो। इसके बाद अगर दोनों टीमें नॉकआउट राउंड में पहुंचती हैं तो दूसरा मैच होता है और कई बार तीसरा मैच यानी फाइनल भी हुआ है। यह सबके लिए फायदे का धंधा होता है। बहरहाल, भारतीय मीडिया यह माहौल बना रहा है कि पाकिस्तान झुक गया। लेकिन यह कोई नहीं बता रहा है कि बीसीसीआई भी चाहता था कि मैच हो और टूर्नामेंट के प्रसारण का अधिकार लेने वाली रिलायंस समूह की कंपनी जियो को भी मैच की जरुरत थी। अगर मैच नहीं होता तो बीसीसीआई को भी नुकसान था और जियो को तो बड़ा नुकसान होता। इसलिए सब चाहते थे कि पाकिस्तान से मैच हो। फिर भी पाकिस्तान ने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि बहिष्कार की घोषणा की।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने बदरा ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582083548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/...)

भाजपा के चौपाला कार्यक्रम में की गई बजट की सराहना

मुरादाबाद।

भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय बुद्धि विहार पर महानगर के नगर विधानसभा में एक चौपाल का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा,महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय,श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष दीप प्र+वलित कर एवं वन्देमातरम गायन कर बजट चौपाल का शुभारंभ किया ।

मुख्य अतिथि क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा ने कहा कि 2014 में मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए होगी गरीबों को राशन मिला बिजली मिली आयुष्मान कार्ड का सैकड़ों योजनाओं का लाभ मिल रहा है मोदी जी ने इन सभी की चिंता की लेकिन विरोधी पार्टियां परेशान होती हैं लेकिन मोदी जी अ'छा कार्य कर रहे है जो काम मोदी जी ने किया कोई भी कर नहीं सकता विदेशों में भारत की साख बढ़ी है । उन्होंने 1फरवरी 2026 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत किया यह बजट मुख्य रूप से युवा,महिला,किसान, शिक्षा, रोजगार,स्वास्थ्य और गरीबों के सशक्तिकरण पर केंद्रित रहा जो कि 2047 तक विकसीत भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए ग्रामीण विकास बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का यह बजट समावेशी विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जिससे ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी।कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला एवं संचालन महानगर उपाध्यक्ष राहुल शर्मा ने किया। चौपाल में वीर सिंह, धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, निमित जयसवाल ,महानगर मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता, दिनेश शीर्षवाल, महानगर उपाध्यक्ष नवदीप टंडन विशाल त्यागी राहुल शर्मा,चंद्र प्रजापति, महानगर मंत्री शम्मी भटनागर, अजय वर्मा,सर्वेश जी पटेल, अनुराग सिंह,अतुल दुबे,मुकेश भारद्वाज, अरविंद सिंह,सुनीता शर्मा, सुनीता सैनी,पूर्णिमा खन्ना, रंजना शर्मा ,हीरा भारती,प्रीति कश्यप,रंजना अग्रवाल,पूनम चौहान, गुड्डी धर्मेश सैनी अभिषेक चौबे किशन लाल जाटव, रजनी कांत जाटव, अभिषेक राठौर मंडल अध्यक्ष कपिल गुप्ता ,विपिन प्रजापति, सोमपाल प्रजापति, विशाल रस्तौगी,मिथुन शर्मा, सूर्य मोहन शमशेरी,वीरपाल सिंह गजेंद्र लोदी,संजय कुमार, सुरेंद्र शर्मा सर्वेश सिंह योगेश गुप्ता,हरिओम सैनी,सौरभ सक्सैना पूरन सैनी दीक्षांत चौधरी,अश्वनी शर्मा जगदीश कश्यप, रमेश सैनी आदि महानगर, मंडल, मोर्चा,प्रकोष्ठों के पदाधिकारीगण एवं पार्षदगण शामिल रहें।

सपा में शामिल हुए मुरादाबाद के कई कांग्रेसी

मुरादाबाद। (वेबवार्ता) कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ पूर्व मंत्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान मुरादाबाद जनपद से भी कई लोगों ने लखनऊ पहुंच कर समाज वादी पार्टी की सदस्यता ली, जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इंजीनियर हाजी सलीम अख्तर और भोजपुर से फहीम चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इन सभी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हम ने लंबे समय से पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम किया लेकिन स्थानीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी का जनपद मुरादाबाद में जनाधार नहीं रहा। सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सऐप पर ही काम हो रहा है हमने शीर्ष नेतृत्व से लखनऊ और दिल्ली जाकर भी अवगत कराया। वहां भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी कारण बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने पार्टी को छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पीसीसी सदस्य मोहम्मद युसुफ खान भी सपाई हो गए।

दिवंगत आरक्षी को पुलिस अफसरों ने दी श्रद्धांजलि

मुरादाबाद।

जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने सोमवार को दिवंगत मुख्य आरक्षी चंद्रपाल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर, ग्रामीण, यातायात मुरादाबाद, क्षेत्राधिकारी लाइन और अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद ने दिवंगत के परिजनों को सांत्वना दी। इसके साथ ही, दिवंगत मुख्य आरक्षी के पार्थिव शरीर को उनके गृह जनपद भिजवाने की व्यवस्था की गई। श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित अधिकारियों ने मुख्य आरक्षी चंद्रपाल सिंह की सेवा और समर्पण को याद किया। उन्होंने उनकी कर्तव्यनिष्ठा को सलाम करते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

भगवान शिव की रुद्राभिषेक की महिमा अपरंपार: पुजारी महेंद्र शास्त्री

मुरादाबाद।

महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के छठे दिन,राष्ट्रीय पुजारी परिषद द्वारा संचालित हिन्दू संस्कार केंद्र प्राचीन शिव मंदिर, लक्ष्मी नगर, पीतल बस्ती मुरादाबाद में,कथा के छठे दिन शिव स्वरूप कथा व्यास पुजारी महेंद्र शास्त्री ने कहा कि भगवान शंकर को अति प्रिय है जल की धार शिव और रुद्र ब्रह्म के ही पर्यायवाची शब्द हैं। शिव को रुद्रा इसलिए कहा जाता है, ये रुत अर्थात दुख को विनष्ट कर देते हैं रुतम,द्रावयति- नाशयतीत रूद्रः उन्होंने कहा कि भक्तों के के सभी प्रकार के दुख व सभी ग्रहों की पीड़ा एवं कुंडली में कल प्रसर्प दोष होने पर भी शांत हो जाता है। रुद्राभिषेक तो अवर्णनीय है। इस जगत में राम से बड़ा दृष्टा और कौन है जिन्होंने लंका जाने के पूर्व राक्षस विध्वंस के लिए स्वयं स्वयं रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर स्वयं रुद्राभिषेक किया और पृथ्वी पर राक्षसों से मुक्त कर शांति की स्थापना की इसी से विदित होता है कि रुद्राभिषेक का कितना महत्व है। जल चढ़ाने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और सभी भक्तों की जल्द से जल्द सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले। सभी भक्त ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे और शिव महापुराण को को सुनकर आनंदित हो रहे थे ।भोलेनाथ से निराला कोई नहीं सारे जग से निराला कोई और नहीं,कथा का पंडाल बीच-बीच में ओम नमः शिवाय के मंत्रो से गूंज रहा था सभी लोग भक्ति भाव से आनंदपूर्वक कथा का रसपान कर रहे थे ।कथा के विश्राम पर भव्य महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया।कथा के मुख्य यजमान हर स्वरूप ,चंद्रभान सैनी रहे कथा की व्यवस्था में पंडित विनोद शर्मा श्याम कृष्ण रस्तौगी संस्थापक राष्ट्रीय पुजारी परिषद शिव कुमार रविंद्र डॉक्टर संजीव प्रजापति जगदीश गणेश मनोज चंद्रपाल हरिओम ठेकेदार , विनीत गुप्ता टैन्ट वाले,कैलाश आदि रहे ।

अशफाक उल्ला खाँ के नाम पर हो जीआईसी ग्राउंड को नाम

कॉलेज की पूर्व छात्र समिति ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

मुरादाबाद।

राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद के पूर्व छात्र समिति द्वारा एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन में मांग की गई कि महानगर मुरादाबाद के राजकीय इंटर कालेज के परिसर ऐतिहासिक तौर पर सूबेदार रुस्तम खां समय स्थापित हुआ ब्रिटिश शासन काल में 1860ई. (राजकीय इंटर कालेज) के रूप में अस्तित्व में आया। आज इसके विशाल परिसर में शिक्षा विभाग के कार्यालय व विधुत विभाग व जर्जर अवस्था में हास्टल व कस्तुरुबा गांधी आवासीय विद्यालय व प्रार्थमिक विद्यालय स्थित है फिर भी कालेज का विशाल परिसर आज भी है। कहा कि राष्ट्रीय खेल हांकी आदि खेलों को सीखकर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश व भारत का नाम रोशन कर राष्ट्र सेवा की भावना से कर रहे हैं भविष्य में भी करते रहेंगे हम ज्ञापन प्रस्तुत कर्ता का सम्बंध इस कालेज से विधार्थी जीवन से है। आज इस कालेज के परिसर मे खेल स्टेडियम बनाना प्रस्तावित है हम सरकार व प्रशासन स्वागत करते हैं तथा शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हुए यह कहना चाहते हैं कि इस कालेज परिसर के प्रस्तावित खेल स्टेडियम का निर्माण महान क्रांतिकारी शहीद ए वतन अशफाक उल्लाह खां ने नाम हो व इस कार्य को शीघ्र अति शीघ्र कराया जाए ताकि गरीब ब'चों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलें । ज्ञापन देने वाले मे मुख्य रूप से मोजूद रहे एड. मो. तनजीम शास्त्री, फिरोज़ खान, एड. अरशद परवेज़ आदि मौजूद।

बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल के कोर्ट ने जारी किये वारंट

मुरादाबाद।

बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ मुरादाबाद की एसीजेएम-5 की अदालत से वारंट जारी हुआ है। कोर्ट की तारीख पर सुनवाई के दौरान मौजूद न होने के कारण अदालत ने अमीषा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अब अभिनेत्री को एसीजेएम-5 की अदालत में 27 मार्च को पेश होने का आदेश दिया गया है। अमीषा पटेल और उनकी पर शिकायतकर्ता ने 11 लाख रुपये लेने के बावजूद कार्यक्रम में न आने का आरोप लगाया गया था। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल और उनकी टीम पर 11 लाख एडवांस लेने के बावजूद एक इवेंट में न शामिल होने का आरोप लगाया गया है। अभिनेत्री को एक शादी में शामिल होकर डांस करने के लिए इनविटेशन दिया गया था, लेकिन एडवांस पेमेंट लेने के बावजूद अमीषा ने इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं की थी।इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाली ड्रीम विजन इवेंट कंपनी के मालिक पवन कुमार वर्मा ने अमीषा पटेल के खिलाफ शिकायत की थी।

इस मामले में मुरादाबाद कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अभिनेत्री के खिलाफ मुरादाबाद कोर्ट में धारा 120-बी, 406,504 और 506 आइपीसी के तहत मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। वह बिना कोई ठोस कारण दिए अदालत में पेश नहीं हुई तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

दरगाह पर हज यात्रियों का किया गया टीकाकरण। उलेमा ने ट्रेनिंग कैम्प में हज के अरकान बताए

बरेली ।

आज दरगाह आला हज़रत पर आज़मीन-ए-हज को ट्रेनिंग देने व टीकाकरण करने के लिए कैम्प का आयोजन किया गया। जिसमें जिले भर से लगभग 100 आज़मीन हज का टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला चिकित्सालय की टीम ने डीआईओ डॉक्टर प्रशांत रंजन नेतृत्व में डॉक्टर साहिबान अली की निगरानी में किया गया। दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि हज यात्रियों की सहूलियत के लिए आज दरगाह पर दरगाह प्रमुख हज़रत मौलाना सुब्हान रज़ा खान (सुब्हानी मिया) की सरपरस्ती व सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन रज़ा क़ादरी(अहसन मियां) की सदारत में दरगाह स्थित मदरसा मंज़र-ए-इस्लाम मे कैम्प का आगाज़ सुबह 10 बजे तिलावत-ए-कुरान से किया गया। बहुत से आजमीन हज वो भी दरगाह पहुंचे जिन्होंने टीका अन्य कैंपों में लगवाया था लेकिन ट्रेनिंग दरगाह पर ली। इसके बाद मुफ्ती जमील व मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी ने हज के अरकान बताते हुए कहा कि 8,9,10,11,12 ज़िल्हिज़्ज़ा हज के अहम दिन है। जिसमे हज के दौरान अदा की जाने वाली रस्में जैसे काबे शरीफ का तवाफ़,अहराम बांधने का सही तरीका,शैतान की कंकड़ी मारने के अलावा सफा और मरवा,मिना अरफात के मैदान में अदा की जाने वाली रस्में व इबादत का तरीका विस्तार से बताया। हज ट्रेनर सुहैल साबरी व रिजवाना खान ने बताया कि किसी हाजी को हज के दौरान कोई मदद चाहिए तो सऊदी हेल्पलाइन नंबर 1966 पर काल कर सकते है। सभी आजमीन हज स्मार्ट फोन चलाने की तैयारी कर ले। साथ ही हज सफर में ले जाने वाले सामान में किया ले जाना है और किया नहीं ले जाना है इसके अलावा हज में बरती जानी वाली सावधानियों के बारे में बताया। दरगाह की ओर से सभी आजमीन हज को हज व जियारत किताब जिसमें हज का तरीका बताया गया है बांटी गई। इस मौके पर दरगाह की ओर से मौलाना अबरार उल हक़,अनवारूल सादात,नाजिम रज़ा, अल्पसंख्यक विभाग से मोहम्मद राशिद के अलावा हाजी ताजुद्दीन, रईस अहमद, आफताब सुहैल, इकबाल अख्तर, स्वास्थ्य विभाग से शाहिद रज़ा, सेहिल सिंह,अंशिका सक्सेना, मोनिका रावत,राखी त्रिपाठी आदि का विशेष सहयोग रहा। शिविर में नवाबगंज, फतेहगंज, मीरगंज, फरीदपुर,आंवला,अलीगंज समेत शहर के आजमीन का टीकाकरण किया गया।

सरकार बताए कि व्यापार समझौता बराबरी के आधार पर हुआ या जबदस्ती - कांग्रेस

नई दिल्ली । कांग्रेस ने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को लेकर सोमवार को नरेन्द्र मोदी सरकार पर भारत के हितों को दांव पर लगाने का आरोप लगाया और कहा कि देश इस बात का जवाब मांग रहा है कि यह समझौता बराबरी के आधार पर हुआ है या जबरदस्ती किया गया है। पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने यह दावा भी किया कि यह समझौता कई अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को खोल देगा तथा इसमें आत्मनिर्भरता के साथ भी समझौता कर लिया गया है। सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, व्यापार समझौते देश की संप्रभुता को त्याग कर, गुलामी का रास्ता कभी नहीं हो सकते। अमेरिका-भारत व्यापार समझौते में मोदी सरकार ने देश और किसानों की बलि दे दी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा से सरेआम खिलवाड़ किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जो किया उससे भारत की डिजिटल स्वायत्तता और डेटा की निजता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि

पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने यह दावा भी किया कि यह समझौता कई अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को खोल देगा

भारतीय हितों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़े होने के बजाय इस मजबूर सरकार ने भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता से समझौता कर लिया। कांग्रेस नेता ने कहा, देश यही सवाल पूछ रहा है कि यह मजबूत

सरकार है या मजबूर सरकार? भारत आत्मनिर्भर है या अमेरिका-निर्भर हो गया? मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में भारत के हित को दांव पर लगा दिया है। उनके मुताबिक, छह फरवरी, 2026 के पहले समझौते के मसौदे में ही सहमति जताई गई है कि भारत बिना किसी आयात शुल्क के अमेरिका के खाद्य व कृषि उत्पादों के लिए हमारा बाजार खोल देगा। सुरजेवाला ने सवाल किया कि अगर भारत में प्रसंस्कृत मक्का, ज्वार, सोयाबीन, फल व अन्य उत्पाद भी आएंगे, तो क्या उनका सीधा प्रभाव भारत की जैविक विविधता और बीज शुद्धता पर नहीं पड़ेगा? उन्होंने दावा किया कि अब अमेरिकी कपास के भारत में निशुल्क आयात का दरवाजा भी मोदी सरकार ने खोल दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा, इसके अलावा, बांग्लादेश भारत से करीब 50 प्रतिशत कपास आयात करता है। मगर अब कपास का भारत से बांग्लादेश को निर्यात भी बंद हो जाएगा, जो कि हमारे किसान पर दोहरी मार होगी। सुरजेवाला ने कहा कि क्या यह देशहित में है कि व्यापार समझौते में अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने की भारत पर पाबंदी लगाई गई है? उन्होंने कहा, यह व्यापार समझौता बराबरी के आधार पर हुआ है या जबरदस्ती के आधार पर, देश जवाब मांग रहा है। कांग्रेस महासचिव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जब भी इस व्यापार समझौते के खिलाफ बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनेगी, तो उससे सभी को अवगत कराया जाएगा।

हरियाणा के 4000 टीचर्स की नौकरी पर खतरा : हुड्डा सरकार में अनुभव के आधार पर हुए थे भर्ती; एचटेट पास नहीं कर पाए

चंडीगढ़ ।

हरियाणा के 4 हजार शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल, ये शिक्षक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में विज्ञापन संख्या 2/2012 के तहत अनुभव के आधार पर नौकरी पाए थे। अब सरकार ने एक बार फिर एचटेट पास नहीं करने वाले प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा सकती है। हालांकि सरकार ने इन शिक्षकों को एक बड़ी राहत देते हुए तय किया है कि यदि ये सभी टीचर्स अगले साल मार्च तक हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर लेते हैं तो इनकी नौकरी जारी रहेगी। मौलिक शिक्षा महानिदेशक की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

4 साल के टीचर अनुभव पर मिली थी नौकरी

हुड्डा की सरकार में विज्ञापन संख्या 2/2012 में निकली भर्ती की एक शर्त के अनुसार 4 वर्ष के शिक्षण अनुभव के आधार पर लगे करीब 4 हजार प्राथमिक शिक्षकों को एक अप्रैल 2015 तक एचटेट पास करना आवश्यक था। इसके बावजूद निर्धारित समयावधि में एचटेट पास नहीं कर सके शिक्षकों को राहत देते हुए 27 अप्रैल 2017 को नया आदेश जारी किया गया।

नियुक्ति पत्र में शामिल होगी शर्त

इसमें सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे ऐसे शिक्षकों के नियुक्ति पत्रों में यह शर्त शामिल करने को कहा गया कि उन्हें भविष्य में एचटेट उत्तीर्ण करना होगा।

हालांकि अप्रैल 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन प्राथमिक शिक्षकों को राहत देते हुए आदेश जारी कर दिए थे कि अब इन्हें भविष्य में एचटेट और बीएड करने की जरूरत नहीं होगी और वे आगे सेवा में बने रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने एचटेट की पात्रता अनिवार्य की

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक सितंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कक्षा पहली से 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी है। यह नियम उन सभी शिक्षकों पर लागू होगा जो 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) एक्ट लागू होने के बाद नियुक्त हुए हैं।

सैनी सरकार ने ये दिया आदेश

इसे देखते हुए मौजूदा प्रदेश सरकार यानी नायब सैनी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का फैसला बदलते हुए निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों ने अभी तक एचटेट पास नहीं किया है, उन्हें मार्च 2027 तक यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसा न करने पर उनकी सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

राजस्थान की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 8 लोग जिंदा जले

भिवाड़ी । राजस्थान के भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में अचानक तेज धमाका हुआ। इसमें 8 मजदूर जिंदा जल गए, जबकि 4 गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। तीन मृतकों की पहचान बिहार के मोतिहारी जिले के मिंटू, नितेश और सुजान के रूप में हुई है। इस फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। मौके से बारूद, पटाखे और पैकिंग के डिब्बे मिले हैं। हादसा खुशखेड़ा कारौली

'अवैध रूप से बन रहे थे पटाखे, 3 मृतकों की हुई पहचान

इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे हुआ। घटना के समय करीब 25 मजदूर काम कर रहे थे। शव बुरी तरह जल गए थे। कई शवों के कंकाल भर बचे थे। बॉडी पार्ट्स के टुकड़े बिखरे मिले। रेस्क्यू टीम ने इन टुकड़ों को पॉलीथीन में इकट्ठा किया। एडीएम सुमिता मिश्रा के अनुसार, फैक्ट्री मालिक का नाम राजेंद्र है। उन्होंने किसी तिवारी को यह फैक्ट्री लीज पर दी थी। दोनों से संपर्क नहीं हो पाया है।

सीएम मान की फिर बिगड़ी तबीयत

चंडीगढ़ ।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सोमवार को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ घंटों बाद ही तबीयत बिगड़ने पर सोमवार शाम दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार मोगा में पार्टी की रैली में शामिल होने के बाद मोहाली पहुंचने पर सीएम मान को सांस लेने में तकलीफ होने लगी जिसके बाद ही तकरीबन रात 8 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले रविवार को भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। संगरूर के धुरी में कार्यक्रम के दौरान उनका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने की बात सामने आई थी जिसके बाद ही उनको

फोर्टिस में भर्ती, मोगा रैली में गए थे, चिकित्सकों की निगरानी में मुख्यमंत्री

एहतियातन मोहाली अस्पताल लाया गया था। अस्पताल स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया था कि मुख्यमंत्री को नियमित जांच के लिए लाया गया। सभी आवश्यक परीक्षण में उनकी स्थिति स्थिर है। अत्यधिक थकान की शिकायत के चलते उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने सीएम के और टेस्ट करवाने की भी सलाह दी थी और अब यह टेस्ट करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दो दिन पहले वह पारिवारिक समारोह में भी शामिल हुए थे।

दिल्ली पुलिस का 79वां स्थापना दिवस

अमित शाह ने दी 10 नई परियोजनाओं की सौगात, सुरक्षा होगी बेहतर

नई दिल्ली ।

दिल्ली पुलिस आज, 16 फरवरी को अपना 79वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

इस विशेष दिन पर, गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस को 10 नई परियोजनाओं की सौगात दी, जिनका उद्देश्य शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दिल्ली पुलिस की 10 नई परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास हुआ है। दिल्ली को 10 हजार कैमरों से जोड़ने के कार्यक्रम के प्रथम चरण में 2100 कैमरे

लाइव जुड़ चुके हैं। दिल्ली में पहले से मौजूद 15 हजार से ज्यादा कैमरों को इसके साथ जोड़ने का काम पूरा हो चुका है। मुझे विश्वास है कि सेफ सिटी योजना आने वाले दिनों में दिल्ली की सुरक्षा को बहुत आगे तक ले जाएगा।

एवेन्यू कोर्ट ने लालू-राबड़ी पर तय किए आरोप, अब चलेगा मुकदमा

नई दिल्ली । सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले के सीबीआई मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए।

लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अदालत में पेश हुए, आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। यह मामला रेलवे ग्रुप डी की नौकरियां उम्मीदवारों को जमीन के बदले दिलाने के कथित अपराध से संबंधित है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय किए। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा, जब तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति न दी जाए। मीसा भारती ने कहा कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए अदालत ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के लिए कहा है। 9 जनवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था। आरोप तय करते समय, सीबीआई की विशेष अदालत ने टिप्पणी की थी, प्रथम दृष्टया, लालू प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में सरकारी नौकरियों का इस्तेमाल करके अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से इच्छुक नौकरी चाहने वालों से अचल संपत्ति हासिल करने की साजिश रची गई थी। अदालत ने आगे कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार एक गिरोह की तरह काम कर रहे थे। अदालत ने मुख्य कार्मिक अधिकारियों (सीपीओ) और रेलवे अधिकारियों सहित 52 आरोपियों को बरी कर दिया। कार्यवाही के दौरान पांच आरोपियों की मृत्यु हो गई। सीबीआई ने 103 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

वो कठपुतली है, जयराम रमेश का तोता है, मणिशंकर अय्यर ने पवन खेड़ा को घेरा; बढ़ा विवाद

नई दिल्ली।

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की तारीफ करने और फिर से सीएम बनने का दावा करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ चुके हैं।

तिरुवनंतपुरम में रविवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम विजयन की मौजूदगी उन्होंने कहा कि पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनके इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया, जिसके बाद पार्टी नेताओं ने उनके इस बयान की आलोचना की। अय्यर के बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और महासचिव व संचार प्रभारी जयराम रमेश की प्रतिक्रिया आई। जिस पर अब मणिशंकर अय्यर ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस नेता अय्यर ने पवन खेड़ा को आड़े हाथों लेते हुए उनको कठपुतली करार दिया, साथ ही कहा कि वो पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता नहीं हैं। उन्होंने दो टूक पवन खेड़ा को एक कठपुतली बताया, जो पार्टी महासचिव जयराम रमेश के कहे अनुसार ही काम करता है।

ये तो बस एक कठपुतली है, पवन खेड़ा पर पलटवार

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पवन खेड़ा प्रवक्ता नहीं बल्कि एक तोता है। राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथी दलों के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर बात करते हुए अय्यर ने कहा कि पवन खेड़ा से बेहतर उम्मीदवार कांग्रेस प्रवक्ता के पद के लिए मौजूद रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप पवन खेड़ा को संदेश भेजें। उन्होंने दिल्ली में एमए बेबी के साथ गठबंधन किया है और यहां पिनराई विजयन के साथ मेरे गठबंधन से उन्हें परेशानी हो रही है। ये किस तरह के कांग्रेसी हैं? सबसे बड़ी बात पवन खेड़ा को प्रवक्ता बनाकर कोई पार्टी कितनी मूर्ख हो सकती है? कांग्रेस में लाखों लोग हैं, जो उनसे बेहतर प्रवक्ता बन सकते हैं। ये तो बस एक कठपुतली है, जयराम रमेश जो कहते हैं वही बोलता है। एक ही बात दोहराता रहता है, ये प्रवक्ता नहीं, तोता है।

पवन खेड़ा मुझे निकालने वाले हैं, तो मैं उनकी पिटाई करूंगा

इतना ही नहीं मणिशंकर अय्यर ने खुद को कांग्रेस पार्टी का सदस्य बताते हुए कहा कि अगर पवन खेड़ा उन्हें पार्टी से निकाल देते हैं, तो वे खुशी-खुशी पार्टी छोड़ देंगे। अय्यर ने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, मैंने इसे नहीं छोड़ा है। अगर पवन खेड़ा मुझे निकालने वाले हैं, तो मैं खुशी-खुशी बाहर जाकर पार्टी छोड़ने के बाद उनकी पिटाई करूंगा।

पवन खेड़ा ने आखिर क्या कहा था?

दरअसल, केरल सीएम की तारीफ करने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पार्टी को अय्यर के बयान से अलग किया। उन्होंने कहा कि अय्यर पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस से जुड़े नहीं हैं। वह केवल अपनी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में बोलते और लिखते हैं।

पीएम मोदी-स्पीकर की वीडियो बनाना कांग्रेस को पड़ा भारी, 9 नेताओं को नोटिस जारी

नई दिल्ली । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार किए गए कथित वीडियो को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी सामग्री साझा करने के आरोप में लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस के नौ नेताओं को नोटिस जारी किया है। इन नेताओं से विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के आरोपों पर तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

9 नेताओं को नोटिस, तीन दिन में जवाब तलब

नोटिस पाने वालों में Jairam Ramesh, Pawan Khera, Supriya Shrinate और Sanjeev Singh सहित कुल नौ नेता शामिल हैं। लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि संबंधित वीडियो साझा किए जाने से सदन की गरिमा और संवैधानिक पदों की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है, इसलिए जवाब आवश्यक है।

एआई वीडियो से बढ़ा विवाद

विवाद की जड़ एक 36 सेकंड का वीडियो है, जिसे सितंबर 2025 में बिहार कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया गया था। इस वीडियो में प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी को राजनीतिक टिप्पणी करते हुए दर्शाया गया था। इसके अलावा दिसंबर में लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्हें कथित तौर पर 'आर्थिक सहायता स्वावलंबन' नामक योजना के तहत आर्थिक मदद की घोषणा करते दिखाया गया। बाद में इसे भी एआई आधारित डीपफेक सामग्री बताया गया।

जांच में सामने आई सच्चाई

सरकारी एजेंसी Press Information Bureau की फैक्ट-चेक इकाई ने जांच के बाद स्पष्ट किया कि वीडियो में छेड़छाड़ की गई थी। मूल वीडियो 1 दिसंबर 2025 का था, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, लेकिन ऑडियो और आवाज को कृत्रिम रूप से बदला गया था। मामले में Delhi Police ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की। वहीं Patna High Court ने कांग्रेस को निर्देश दिया कि संबंधित वीडियो को तत्काल सोशल मीडिया से हटाया जाए।

एआई और राजनीति – नई चुनौती

इस घटनाक्रम ने एक बार फिर राजनीति में एआई और डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल दौर में फर्जी सामग्री तेजी से फैलती है, जिससे जनमत और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर असर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में इस मामले पर जवाब और कार्रवाई राजनीतिक बहस को और तेज कर सकती है।

अब एआई बनेगा भारत की नई शक्ति!

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी राजधानी राजधानी के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया। यह एक्सपो 16 से 20 फरवरी तक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के साथ आयोजित किया जाएगा और इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्यावहारिक उपयोग को प्रदर्शित करने वाले एक राष्ट्रीय मंच के रूप में देखा जा रहा है, जो नीति निर्माण, नवाचार और व्यापक कार्यान्वयन को एक ही मंच पर लाएगा। 70,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 10 क्षेत्रों में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां, स्टार्टअप, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय भागीदार भाग ले रहे हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान जियो एआई पवेलियन में जियो के चेयरमैन

भारत मंडपम से पीएम मोदी ने किया Tech Revolution का शंखनाद

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026- 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और 500 ग्लोबल एआई विशेषज्ञ ले रहे हिस्सा

आकाश अंबानी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने

स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और स्मार्ट होम सॉल्यूशंस के क्षेत्र में कंपनी के एआई-आधारित परिवर्तन का प्रदर्शन किया। 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और 500 वैश्विक एआई नेता एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हुए। एआई इम्पैक्ट समिट तीन मूलभूत स्तंभों या सूत्रों पर आधारित है- लोग, ग्रह और प्रगति। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो में 30 देशों के 300 से अधिक प्रदर्शकों के 10 से अधिक विषयगत पवेलियनों में भाग लेने की उम्मीद है। भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए

नई दिल्ली में सोमवार से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का शानदार शुरूआत हो गई है। इस वैश्विक सम्मेलन में दुनिया भर के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सरकार के प्रमुख और मंत्री शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा तकनीकी क्षेत्र के दिग्गज, शोधकर्ता और उद्योग जगत के विशेषज्ञ भी इस मंच पर जुटे हैं। इस समिट का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करना है। इसके जरिए समावेशी विकास, मजबूत सार्वजनिक व्यवस्था और सतत विकास को बढ़ावा देने की योजना है। यह अपनी तरह का पहला बड़ा वैश्विक सम्मेलन है, जिसका आयोजन ग्लोबल साउथ के किसी देश में हो रहा है। यह सम्मेलन पांच दिनों तक चलेगा और 20 फरवरी को इसका समापन होगा। इसमें 100 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख शामिल हैं। साथ ही 60 मंत्री और उपमंत्री भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सम्मेलन में 500 से अधिक वैश्विक एआई विशेषज्ञ भी आए हैं। इनमें बड़ी कंपनियों के सीईओ, संस्थापक, शिक्षाविद, शोधकर्ता और परोपकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को इस समिट में शामिल होंगे। वह वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। उनके इस संबोधन से वैश्विक सहयोग और भारत की समावेशी एआई सोच को एक नई दिशा मिलेगी। भारत हमेशा से जिम्मेदारी से एआई के इस्तेमाल का पक्षधर रहा है।

प्रभाव-उन्मुख और जन-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, जिसमें मापने योग्य सामाजिक और आर्थिक परिणामों को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। यह शिखर सम्मेलन तीन मूलभूत स्तंभों पर आधारित है, जिन्हें सूत्र कहा जाता है - एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है मार्गदर्शक सिद्धांत या आवश्यक सूत्र जो ज्ञान और कर्म को आपस में जोड़ते हैं। ये सूत्र परिभाषित करते हैं कि किस प्रकार बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से सामूहिक लाभ के लिए एआई का उपयोग किया जा सकता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप केंद्रित और परिणामोन्मुखी परिणाम दे रहा है। यह समिट सरकार और उद्योग जगत में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक एआई तैनाती, नीतिगत सामंजस्य और संस्थागत समन्वय को बढ़ावा दे रहा है।

यह शासन और नियामक ढांचों को मजबूत कर रहा है, एआई-आधारित औद्योगिक विकास के लिए क्षेत्रीय तैयारियों का आकलन कर रहा है और कौशल विकास एवं कार्यबल परिवर्तन को गति दे रहा है। यह समिट एआई अनुप्रयोगों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है और एआई पारिस्थितिकी तंत्र के जिम्मेदार, समावेशी और नवाचार-संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और उद्योग के बीच स्थायी साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है।